

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

11/10/97

सं० 183]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितंबर 19, 1997/भाद्र 28, 1919

No. 183]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 19, 1997/BHADRA 28, 1919

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1997

फा. सं. 22/5/97-बि. क. :—4 जुलाई, 1997 को हुए वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में एक संकल्प को अपनाया गया था जिसमें राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के एक कार्यदल का गठन किए जाने की सिफारिश की गयी थी ताकि सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में मूल्य वर्धित कर लागू किए जाने के सम्बन्ध में हुई प्रगति एवं समय-सीमा पर विचार किया जा सके।

2. इस संकल्प के अनुसरण में, सरकार के भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के दिनांक 4-7-1994 के संकल्प फा. सं. 31/56/93-बि. क. के तहत गठित राज्यों के वित्त मंत्रियों की इस समिति को यह कार्य सौंपने का निर्णय किया है। इस समिति में सार्वजनिक वित्त एवं नीति सम्बन्धी राष्ट्रीय संस्थान, नई दिल्ली तथा किसी ऐसे संगठन, जो आवश्यक समझा जाए, से लिए गए विशेषज्ञ कार्य करेंगे।

3. यह समिति अपने कार्य के लिए अपनी ही प्रक्रियाएं तैयार करेगी तथा यह राज्य सरकारों/संघ शासित राज्य सरकारों से सूचना मंगवा सकेगी जो आवश्यक हो।

4. सार्वजनिक वित्त एवं नीति सम्बन्धी राष्ट्रीय संस्थान इस समिति को सचिवालयीय सहायता उपलब्ध करायेगा।

5. यह समिति तीन महीनों के भीतर अपना विचार-विमर्श पूरा कर लेगी ताकि राज्यों एवं संघ-शासित राज्यों के वित्त मंत्रियों के आगामी सम्मेलन में इसकी रिपोर्ट पर विचार/विमर्श किया जा सके।

एस. एस. डावरा, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

RESOLUTION

New Delhi, the 19th September, 1997

F. No. 22/5/97-ST:—The Finance Ministers' Conference held on 4th July, 1997 had adopted a resolution recommending constitution of a working group of Finance Ministers of States and Union Territories to evaluate the progress made towards and chart a time path to introduction of VAT in all the States and Union Territories.

2. In pursuance of the resolution, Government has decided to entrust this job to the Committee of State Finance Ministers constituted vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue's Resolution F. No. 31/56/93-ST dated the 4th July, 1994. The Committee will be serviced by experts drawn from the National Institute of Public Finance & Policy, New Delhi and any other organisation as may be considered necessary.

3. The Committee will evolve its own procedures for its work and may call for information as may be necessary from State Governments/Union Territories.

4. The National Institute of Public Finance & Policy will provide secretarial assistance to the Committee.

5. The Committee will complete its deliberations within three months so that its Report can be considered at the next Conference of the Finance Ministers of States and Union territories.

S. S. DAWRA, Addl. Secy.

